लोक प्रशासन में
उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार

Prime Minister's Awards for Excellence in Public Administration

2009 - 2010

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
भारत सरकार

Department of Administrative Reforms and Public Grievances
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Government of India

विषय-सूची

1. वर्ष 2009-2010 के लिए पुरस्कार विजेता

   (i) दूरियों को पाटता-बिहार राज्य पुल निर्माण निगम का कायापलट-एक सफल कहानी 1-2

   (ii) मल्कापुर 24×7 जल आपूर्ति स्कीम की सफलता की कहानी 3-4

   (iii) शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्र (ईटीसी) - स्वप्न से यथार्थ 5-6

   (iv) सिकल सेल ऐनिमिया कंट्रोल प्रोग्राम, गुजरात सरकार 7-8

   (v) हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक कचरे का स्थायी प्रबंध संकल्पना से नीति तक 9-10

2. वर्ष 2008-09 के लिए पुरस्कार विजेता 11-13

3. वर्ष 2007-08 के लिए पुरस्कार विजेता 14-16

4. वर्ष 2006-07 के लिए पुरस्कार विजेता 17-21

5. वर्ष 2005-06 के लिए पुरस्कार विजेता 22

CONTENTS

1. Awardees for the Year 2009-10
    - (i) Bridging the Gap - The Turn around of Bihar Rajya Pul Nirman Nigam – A Success Story 1-2
    - (ii) Success Story of Malkapur 24×7 Water Supply Scheme 3-4
    - (iii) Education and Training Centre (ETC) - Dreams to Reality 5-6
    - (iv) Sickle Cell Anemia Control Programme, Government of Gujarat 7-8
    - (v) Sustainable Plastic Waste Management in Himachal Pradesh: From Concept to Policy 9-10
2. Awardees for the Year 2008-09 11-13
3. Awardees for the Year 2007-08 14-16
4. Awardees for the Year 2006-07 17-21
5. Awardees for the Year 2005-06 22

पहल – दूरियों को पाटता – बिहार राज्य पुल निर्माण निगम का कायापलट – एक सफल कहानी

पुरस्कार विजेता का नाम – श्री प्रत्यय अमृत, भा.प्र.से., सचिव
राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना

1975 में स्थापित राज्य पुल निर्माण निगम (आर पी एन एन) 2005 तक एक निष्क्रिय संगठन था। रा. पु. नि. नि. गैर योजना व्यय के आधिक्य, बजट बाध्यताओं, कुछ परियोजनाओं तथा कम कार्य निष्पादन जैसी समस्याओं से ग्रस्त था जिसके परिणामस्वरूप इससे कम लाभ प्राप्त हुआ। 2006 तक सरकार ने रू. 17 करोड़ के घाटे को देखते हुए संगठन को बन्द करने का निर्णय लिया।

श्री प्रत्यय अमृत ने अप्रैल, 2006 में अध्यक्ष, रा. पु. नि. नि. का कार्यभार संभाला। शुरू के तीन माह कर्मचारियों के साथ पारस्परिक क्रिया, क्षेत्र दौरों, सफल संगठनों के अध्ययन आदि में बिताए गए। संगठनों के आधार पर कार्यवाई शुरू की गई। निष्कर्षों के आधार पर दो कार्यवाई शुरू की गई – परिसमापन याचिकाओं को वापस लेना तथा निदेशक मंडल को पुनर्जीवित करना। चूंकि कर्मचारी अनियमित रूप से वेतन प्राप्त करने की समस्या का सामना कर रहे थे इसलिए राज्य मंत्रिमंडल ने प्रतिशत प्रभार के निर्धारण की मंजूरी दी। कार्यकुशल अभियंताओं की पहचान की गई और उन्हें तैनात किया गया। स्थापना लागत पर बिना किसी अतिरिक्त भार के कुछ नये प्रभाग बनाये गये। अभियंताओं को वाहन, जनरल पैकेज रेडियो सेवा (जीपीआरएस) परिचालित मोबाइल फोन और प्रशासनिक स्वतंत्रता दी गई जिससे वे प्रेरित हुए। फोन का सॉफ्टवेयर मोबाइल इन्सपेक्टर नामक सॉफ्टवेयर के साथ लगाया गया जिससे कि मुख्यालय से कार्य स्थल पर किए गए वास्तविक कार्य का मूल्यांकन किया जा सके। मुख्यालय पर ऑनलाइन मॉनीटरिंग की व्यवस्था की गई और सहायक अभियन्ता से नीचे के अधिकारियों को लैपटॉप उपलब्ध कराए गए। ठेकेदारों और तृतीय पक्ष गुणवत्ता परामर्शदाताओं की उपस्थिति में अभियंताओं के साथ, मासिक बैठकें की गई। गुणवत्ता प्रयोगशाला का नवीनतम उपकरणों से आधुनिकीकरण किया गया और तृतीय पक्ष गुणवत्ता जांच शुरू की गई। अभियंताओं को प्रेरित करने के लिए पेशेवरों को काम पर लगाया गया। अन्य प्रेरणा प्रयासों में सामुदायिक मध्याह्न भोजन, प्रमुख उत्सवों का आयोजन, योग शिविर, जीवन कला सत्र, व्यायामशाला की स्थापना आदि सम्मिलित थे। बुद्धिशीलता सत्र नियमित अन्तरालों पर संचालित किए

Category - Individual

Initiative - Bridging the Gap - The Turn around of Bihar Rajya Pul Nirman Nigam – A Success Story

Name of the Awardee - Shri Pratyaya Amrit, IAS, Secretary,
Rajya Pul Nirman Nigam Ltd., Patna

Rajya Pul Nirman Nigam (RPNN), established in 1975, was a defunct organization by 2005. RPNN was plagued by problems like excess of non-plan expenditure, budget constraints, few projects and poor execution, which resulted in low profitability. By 2006, the Government decided to wind up the organization, owing to losses of Rs.17 crore.

Shri Pratyaya Amrit took charge as the Chairman of RPNN in April, 2006. The first three months were spent in interacting with employees, field visits, studying successful organizations, etc. Based on the findings, two steps were initiated – withdrawal of liquidation petition and revival of the Board of Directors. As the employees were grappling with irregular salaries, the state cabinet approved fixation of percentage charge. Engineers with right skills were identified and posted. A few new divisions were created without any extra burden on establishment cost. The engineers were provided with vehicles, General Packet Radio Service (GPRS) enabled mobile phones and administrative freedom, which motivated them. The phones were installed with software called Mobile Inspector, through which photographs of the actual work at site could be accessed at the Headquarters. Online monitoring was installed at the Headquarters and officers down to the rank of Assistant Engineers were provided with Laptops. Monthly review meetings were conducted with the engineers in the presence of contractors and third-party quality consultants. Quality laboratory was modernized with latest equipment, and third-party quality check was introduced. Professionals were roped in to motivate the engineers. Other motivation efforts included community lunches, celebrating major festivals, yoga camps, Art of Living sessions, setting up gymnasium, etc. Brain storming sessions were conducted at

गए। लम्बित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए विदेश यात्रा हेतु अवकाश सहित अनेक प्रोत्साहन शुरू किए गए।

सभी लंबित पुलों को दिसम्बर 2008 तक पूरा कर लिया गया तथा घाटे में जा रहा निगम कर्ज से उबरा। निगम प्रारंभिक लक्ष्यों के रूप में कार्य को समय पर पूरा करने और गुणवत्ता की वचनबद्धता को पूरा करने से एक आई एस ओ 9001 और आई एस ओ 14001 प्रमाणित कम्पनी बन गया। 12 जून 2008 को पूरे राज्य में निगम द्वारा बनाये गए सभी 140 पुलों का एक साथ ही उद्घाटन किया गया। गत राजस्व वर्ष में निगम को 80 करोड़ रूपये का लाभ हुआ। निगम ने – गतिविधियों का विस्तार कई नई क्षेत्रों में भी किया जैसे कि सड़क और भवन निर्माण, सिंचाई परियोजनाओं, राज्य की राजधानी का सौंदर्यीकरण तथा पटना सड़क परियोजना।

regular intervals. Several incentives were introduced including vacation to a foreign destination for completing pending projects speedily.

All the pending bridges were completed by December 2008 and the loss making corporation came out of debt. RPNN became an ISO 9001 and ISO 14001 certified company with overriding commitment to timely completion and quality maintenance as primary goals. On June 12, 2008, 140 bridges built by RPNN across the state were inaugurated in one go. RPNN posted a profit of Rs.80 crore in the last fiscal year. It diversified into new sectors like roads and building construction, irrigation projects, beautification of State Capital, and Patna Roads Project.

पहल – मल्कापुर 24×7 जल आपूर्ति स्कीम की सफलता की कहानी

पुरस्कार विजेताओं का नाम – 1. श्री राजेंद्र गणेशलाल होलाणी
मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण,
क्षेत्र औरंगाबाद

2. श्री सदानद काशीनाथ भोपाले,
सेक्शन अभियंता

3. श्री सुनील यशवन्त बासुगडे,
सेक्शन अभियंता

4. श्री उत्तम पांडुरंग बागडे,
सेक्शन अभियंता,
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण,
कार्य प्रभाग, कराड़,
जिला: सतारा

1988 में शुरू की गई मल्कापुर कस्बे के लिए नलों के जरिए जल आपूर्ति की योजना में सन 2010 तक 14000 की अनुमानित जनसंख्या वृद्धि के आधार पर 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) जलापूर्ति की परिकल्पना की गई थी। लेकिन कस्बे की आबादी अनुमानित समय से 10 वर्ष पहले ही अनुमानित वृद्धि से 50 प्रतिशत अधिक बढ़ गयी। इसके परिणामस्वरूप जलापूर्ति सेवा खराब और अस्त-व्यस्त हो गई। इस समस्या से निपटने के लिए ''वाटर जेम्स'' सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके एक डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क डिजाइन किया गया ताकि चौबीसों घंटे पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। ग्राम पंचायत के सदस्यों को शामिल करके पाइप बनानें की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया, इससे पाइपों की गुणवत्ता सुनिश्चित हुई। इन पाइपों के निर्माण के लिए प्रयुक्त की जाने वाली राल से संबंधित प्रणाली के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी और इस प्रणाली को एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से प्राप्त किया गया था। तीसरे पक्ष द्वारा निरीक्षण, ठेके की एक आवश्यक पूर्व शर्त थी, इसके अनुसार एक निरीक्षण एजेंसी द्वारा इन पाइपों की जांच करायी गई और इन्हें प्रमाणित कराया गया। इस प्रकार यह सुनिश्चित किया गया कि

Initiative - Success Story of Malkapur 24×7 Water Supply Scheme

Name of the Awardees -

1. Mr. Rajendra Ganeshlal Holani
   Chief Engineer, Maharashtra Jeevan Pradhikaran, Region Aurangabad
2. Mr. Sadanad Kashinath Bhopale,
   Section Engineer
3. Mr. Sunil Yashwant Basugade,
   Section Engineer
4. Mr. Uttam Pandurang Bagade,
   Section Engineer
   Office of the Executive Engineer,
   Maharashtra Jeevan Pradhikaran,
   Works Division, Karad,
   District: Satara.

Malkapur town piped water supply scheme, commissioned in 1988 was envisaged to supply 40 liters per capita per day (LPCD) on the basis of an estimated population growth of 14,000 by 2010. But the town's population increased 50% more than the estimated growth and 10 years earlier than the projection. This resulted in poor and unreliable supply of water and untimely service. To overcome this problem, a distribution network was designed using "Water Gems" software ensuring '24x7 availability'. The transparent process of manufacture of pipes involving the village Panchayat-members ensured quality. The methodology regarding the resin to be used for manufacturing these pipes was tendered and accredited by an international agency. Third party inspection, an essential pre-requisite as per the tender, was carried out and certified by an inspection agency. Thus, it was ensured that the pipes used for connections conformed to relevant ISO standards. Similarly, Automatic Meter Readers (AMR meters) used in

कनेक्शन में उपयोग होने वाले पाइप आई.एस.ओ. के तत्संबंधी मानकों के अनुरूप हों। इसी प्रकार परियोजना में उपयोग होने वाले ऑटोमेटिक मीटर रीडरों (एएमआर) की भी तीसरे पक्ष से जांच करायी गई। पाइप लाइन बिछाने की सुव्यवस्थित योजना बनायी गई और चरणबद्ध तरीके से अलग क्षेत्रों में पाइप बिछा कर यह कार्य समय पर पूरा कर लिया गया। स्थानीय लोगों, स्टेकहोल्डरों और जनप्रतिनिधियों ने विशेष अभियान चलाकर लोगों को सही टोंटियां लगाने के लिए समझाया। पानी के आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए वृद्धिगत/टेलीस्कोपिक जल शुल्क प्रणाली शुरू की गई।

इस पहल से जलापूर्ति सेवा और समय दोनों में सुधार हुआ। दिन रात अच्छे दबाव के साथ पानी की सप्लाई से जलापूर्ति की गुणवत्ता भी बेहतर हो गई। टेलीस्कोपिक शुल्क ढांचे और प्रतिदिन जलापूर्ति के 19-20 घंटों को क्रमिक रूप से घटाकर 13-14 घंटे करने से पानी की बर्बादी में 30 प्रतिशत की कमी आई। एएमआर टाइप मीटर लगा कर बिलिंग प्रक्रिया आसान बनाई गई और यह सुनिश्चित किया गया कि मीटर रीडर अपने हाथ में पकडे हुए रेडियो फ्रीक्वेंसी से चलने वाले छोटे से उपकरणों के जरिए दूर से ही रीडिंग ले लें। अब छतों पर रखी गई टंकियों तक पानी पम्प करने की आवश्यकता नहीं रह गई थी, बिजली की खपत काफी कम हो गई और वातावरण में कार्बन डाइआक्साइड के उत्सर्जन में लगभग 450 टन तक की कमी आने से प्रदूषण में कमी हुई। ऑटोमेशन प्रणाली में जीएसएम प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया, इससे संचालन लागत में कमी आई और पम्प ऑपरेटरों की आवश्यकता नहीं रही।

the project too were third-party inspected. Laying the pipelines was properly planned, and phased zone-wise execution was completed in time. Local residents and stakeholders including the public representatives undertook a special drive to convince people to fix proper stop-cocks. Progressive / telescopic water tariff system was introduced to curb excessive usage of water.

This initiative improved the delivery time and services of water supply. It also contributed to good quality of water-delivery as a result of pressurized water throughout the day and night. 30% reduction in wastage of water was ensured with telescopic tariff structure and with gradual decrease in the number of hours of water supply from 19-20 hours to 13-14 hours per day. Simplification of billing procedure with AMR type meter installation ensured that reading could be taken remotely by driving through the streets using radio-frequency driven hand-held devices. As the pumping of water to the water tank on terraces was not required, use of electricity was remarkably reduced leading to energy conservation and reduction in pollution, to an estimated extent of 450 tons of carbon dioxide in the atmosphere. The system of automation using GSM technology reduced the cost of operation and eliminated the requirement of pump operators.

पहल - शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्र (ईटीसी) - स्वप्न से यथार्थ

पुरस्कार विजेताओं का नाम - 1. श्री विजय शांतीलाल नाहटा
भा. प्र. से., नगर आयुक्त
नवी मुम्बई नगर निगम
(एनएमएमसी)

2. सुश्री वर्षा विश्वजीत भगत
निदेशक - (ईटीसी)

वर्ष 2007 में बधिर बच्चों के लिए एक शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्र शुरू किया गया था और अन्य प्रकार की अशक्तताओं की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए बाद में इसका विस्तार कर दिया गया था। इससे शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्र के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। अध्यक्ष के रूप में नवी मुम्बई के आयुक्त सहित एक प्रबंध समिति ने शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्र के लिए कार्य नीतियों की रूप रेखा तैयार की। प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थियों को ध्यान से देखा गया और मूल्यांकन किया गया; तथा माता-पिता से उनके बच्चों को शिक्षित करने में उनकी भूमिका के बारे में विचार-विमर्श किया गया। प्राप्त सूचना की वैधता और घर के माहौल की जांच करने के लिए घर का दौरा किया गया। चिकित्सीय उपचार के लिए कई अनुरोधों के आधार पर बाह्य रोगी विभाग और उपचारात्मक शिक्षा के लिए यूनिट बनायी गई तथा बधिर, बौद्धिक अशक्तता, बहु अशक्तताओं और ज्ञान अशक्तता वाले बच्चों के लिए विभिन्न अनुभाग शुरू किए गए। उपचारात्मक शिक्षा यूनिट और पूर्व व्यवसायिक यूनिट भी शुरू की गई। केन्द्र ने वर्दी, शिक्षण अध्ययन सामग्री, उपकरण आदि दिए। विशेष बच्चों के लिए उनकी जरूरतों पर विधिवत विचार करके द्वार से द्वार परिवहन दिया गया और पोषक तथा स्वादिष्ट भोजन दिया गया। ऑडिटरी वर्बल थेरेपी, स्पीच लेंग्वेज थेरेपी, फिजियो थेरेपी, व्यवसायिक थेरेपी जैसी विभिन्न थेरेपियो, माता-पिता प्रशिक्षण एवं मार्ग निर्देश का संचालन किया गया। अशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को पुनः जीवित किया गया।

शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्र ने आम लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम, रैलियां, कार्यशालाएं, नुक्कड नाटकों का आयोजन किया और पुस्तिका, लेख और इस्तहार भी वितरित किए। वर्ष 2009-10 के दौरान पुरस्कार और

Category - Team

Initiative - Education and Training Centre (ETC) - Dreams to Reality

Names of the Awardees -

1. Mr. Vijay Shantilal Nahata, IAS
   Municipal Commissioner,
   Navi Mumbai Municipal Corporation
   (NMMC)
2. Ms. Varsha Vishwajeet Bhagat,
   Director - ETC

An Education and Training Centre for children with hearing-impairment was started in 2007 and later expanded to cater to other types of disabilities. This led to formation of ETC. A Management Committee with the Commissioner of Navi Mumbai as the Chairman designed strategies for ETC. Students seeking admissions were observed and assessed, and the parents counseled about their role in educating their child. A home-visit was made to validate the information received and check the environment at home. Based on several requests for therapeutic treatment, units for OPD and remedial education were built and various sections for children with hearing-impairment, intellectual-impairment, multiple impairments and learning-disability were started. Remedial education unit and pre-vocational unit were also started. The Centre provided uniform, teaching-learning material, appliances etc. Door-to-door transport was provided for special children and nutritious and tasty meals were served to them, duly considering their requirements. Various therapies like auditory verbal therapy, speech-language therapy, physiotherapy, occupational therapy, parent training and guidance were conducted. The process of issuance of disability certificates was also revamped.

ETC organized community-based rehabilitation programs, rallies, workshops, street-plays, and also distributed booklets, articles and pamphlets to create awareness among general public. Awards and reward schemes were

ईनाम योजनाओं को कार्यान्वित किया गया और कई आरोपण एवं दोष निवारण शल्यचिकित्सा शुरू की गई। विकलांगों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता तथा स्व–रोजगार तथा शैक्षणिक सहायता के लिए धनराशि प्रदान की गई। इन बच्चों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की प्रदर्शनियां आयोजित की गई और नवी मुम्बई नगर निगम और शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा अशक्त व्यक्तियों की भर्ती की गई।

implemented during 2009-10 and several implant and corrective surgeries undertaken. Financial help for marriage of handicapped people and funding for self-employment and educational support were extended. Exhibitions of articles made by these children were organized and persons with disability were recruited by NMMC and ETC.

पहल – सिकल सेल ऐनिमिया कंट्रोल प्रोग्राम, गुजरात सरकार

संगठन का नाम – स्वास्थ्य, चिकित्सा सेवाएँ एवं चिकित्सा शिक्षा आयुक्तालय, गांधीनगर, गुजरात

लाल रक्त कोशिकाओं की विकृति से जनित रक्ताल्पता यानी सिकल सेल ऐनिमिया (एससीए) का रोगी आजीवन पीड़ित रहता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आईसीएमआर) द्वारा कराये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार दक्षिण गुजरात की कोलचा, कोटवाड़िया और कठोड़ी आदिम जनजातियों में एससीए से पीड़ित 30 प्रतिशत बच्चे 14 वर्ष की आयु से पहले ही गुजर जाते है और शेष 70 प्रतिशत की 50 वर्ष की उम्र तक पहुंचते मौत हो जाती है। वर्ष 2005–06 में, गुजरात सरकार के स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग ने दक्षिण गुजरात के 4 जिलों में एससीए नियंत्रक कार्यक्रम शुरू करने के बारे में एक संकल्प पारित किया था। वर्ष 2010 मे, इसके दायरे में गुजरात के सभी 12 जनजातीय जिलों को शामिल कर लिया गया।

प्रारंभ में दक्षिण गुजरात के 4 जनजातीय जिलों से सरकार और गैर सरकारी संगठनों के 78 संस्थानों को कार्यक्रम में शामिल किया गया था। दिसम्बर 2010 तक, गुजरात के 12 जनजातीय जिलों में एससीए रोगियों की गहन देखभाल करने वाले केन्द्रों की संख्या 414 तक पहुंच गई थी। गुजरात सरकार ने राज्य की सम्पूर्ण 61.62 लाख जनजातीय आबादी का 5 वर्ष के अंदर सिकल सेल स्क्रीनिंग कराने का चुनौतीपूर्ण कार्य शुरू किया है। इस पर 24.76 करोड़ रूपये की लागत आयेगी। यह कार्य सरकारी–गैर सरकारी संगठन सार्वजनिक निजी भागीदारी अर्थात् भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी और गैर–सरकारी संगठन, वलसाड रक्तन केन्द्र के साथ साझेदारी से शुरू किया गया था। स्क्रीनिंग में सभी आयु समूह को शामिल किया गया था लेकिन किशोरो की स्क्रीनिंग, प्रसव–पूर्व स्क्रीनिंग और नवजात शिशुओं की स्क्रीनिंग (एनबीएस) पर विशेष जोर दिया गया था। सरकार ने वलसाड़ में हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी (एचपीएलसी) आधारित एनबीएस–वैरियंट मशीनें स्थापित की और नवजात शिशुओं के ऐड़ी में छेदन से फिल्टर पेपर पर लिये गये रक्त के शुष्क नमूने से एससीए की जांच के लिए एनबीएस स्क्रीनिंग का कार्य शुरू किया

Initiative - Sickle Cell Anemia Control Programme, Government of Gujarat

Name of the Organization - Commissionerate of Health, Medical Services & Medical Education, Gandhinagar, Gujarat

Sickle Cell Anemia (SCA) patients suffer throughout their lives right from their birth. According to a survey conducted by Indian Council for Medical Research (ICMR), amongst the primitive tribes of south of Gujarat, viz. Kolcha, Kotwadia & Kathodi, 30% of SCA-affected children die before they reach 14 years and the remaining 70% die by the age of 50. In the year 2005-06, the Department of Health & Family Welfare of Government of Gujarat (GoG) passed a resolution to initiate SCA Control Program in 4 districts of south Gujarat. In 2010, it was extended to all 12 tribal districts of Gujarat.

Initially, 78 Government and NGO Institutions were involved in the program from 4 tribal districts of south Gujarat. As of December 2010, there were 414 centers across the 12 tribal districts of Gujarat that were involved in comprehensive care of SCA patients. The Government has taken up the challenging task of Mass Sickle Cell Screening of all 61.62-lakh tribal population of Gujarat within 5 years at a cost of Rs. 24.76 crore. This work was initiated with Government-NGO public-private partnership – i.e. partnership with Indian Red Cross Society and Valsad Raktan Kendra, an NGO. The screening included all age groups along with special emphasis on adolescent screening, antenatal screening and New Born Screening (NBS). The Government installed High Performance Liquid Chromatography (HPLC) based NBS-Variant machine at Valsad and initiated NBS screening for SCA detection from dry blood samples collected on filter paper from heel prick of new born babies. The Government of Gujarat signed an MOU with GIOSTAR, a USA-based company for creating stem cell faculties at

गया गुजरात सरकार ने सूरत के सरकारी मेडिकल कॉलेज में स्टेम सेल सुविधाएं स्थापित करने के लिए यूएसए की कम्पनी जीओस्टार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। स्टेम सेल प्रत्यारोपण ने गुजरात के इन रोगियों में जीवित रहने की आशा फिर से जगा दी। पीएचसी, सीएचसी और उप केन्द्रों के माध्यम से फॉलिक ऐसिड और रक्त निवारक जैसी बुनियादी औषधियों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की गई। स्थानीय भाषा में बैनर, पम्फलेट, फिल्में और तुकबंदियां जैसी आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) सामग्री पीएचसी के उपकेन्द्रों सहित सभी स्तरों पर उपलब्ध करायी गयी।

सिकल सेल बीमारी की मौजूदगी का पता लगने से फरवरी, 2006 से जून, 2010 तक कुल 10, 69, 475 जनजातीय लोगों को इस कार्यक्रम से लाभ पहुंचा 8, 116 (0.76 प्रतिशत) एससीए मरीजों की पहचान की गई और इनका उपचार किया गया। उन्हें आवश्यकता परामर्श भी दिया गया। सिकल सेल ट्रेट वाले 1, 36, 759 (12.79 प्रतिशत) व्यक्तियों को जहां कहीं भी जरूरी हुआ, आवश्यक परामर्श दिया गया, युवाओं को भी विवाह के बारे में परामर्श दिया गया। इसके परिणामस्वरूप, गुजरात के जनजातीय लोगों में जबरदस्त जागरूकता नजर आ रही है, वे पैतृक निदान और नवजात स्क्रीनिंग कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इस प्रकार इस आनुवंशिक विकृति की वजह से होने वाली अस्वस्थता दर और मृत्यु दर में गिरावट आई है।

the Government Medical College, Surat. Stem cell transplantation brought back hope of survival for these patients in Gujarat. Consistent and uninterrupted supplies of basic medicines like folic acid and painkillers were assured through PHCs, CHCs and Sub centers. IEC (Information, Education and Communication) materials like banners, pamphlets, movies, and jingles were created in vernacular language and made available at all levels including at sub centers of PHCs.

From February 2006 to June 2010, a total of 10,69,475 tribal people benefited from this programme, by way of diagnosis for presence of of Sickle Cell Disease. 8,116 (0.76%) SCA patients were identified and were given necessary treatment. They were also provided necessary counseling. 1,36,759 (12.79%) individuals with Sickle Cell Trait were provided necessary counseling and wherever necessary, marriage counseling was also done amongst youngsters. As a result, tremendous awareness is noticeable amongst tribal people of Gujarat by way of their participation in prenatal diagnosis and new born screening program, thereby reducing morbidity and mortality as a result of this genetic disorder.

पहल – हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक कचरे का स्थायी प्रबंध संकल्पना से नीति तक

संगठन का नाम – पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी ई एस टी), हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यावरण को सुरक्षित रखने और उसकी सुरक्षा करने के लिए जागरूकता पैदा करने की कार्यवाई करने और इसका समर्थन करने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभायी है और पहल की है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और अन्य विकास अनिवार्यताओं के परिणामस्वरूप इस पहल को कार्यान्वित करने में एक बडी चुनौती सामने आई। अप्रैल, 2009 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक के प्रयोग को नियंत्रित करने और इसके निपटान के लिए एक व्यापक स्थायी प्लास्टिक कचरा प्रबंध योजना की दिशा में काम करने का निर्णय लिया।

यह पहल तीन चरणों में शुरू की गई थी:

चरण–I (अप्रैल' 09 – नवम्बर' 09) – एक सक्षम ढांचे का निर्माण: पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, दिल्ली के विशेषज्ञों के साथ एक प्रौद्योगिकीय समाधान हेतु सड़क निर्माण में प्लास्टिक के प्रयोग की एक लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी तैयार की जिसके परिणामस्वरूप सड़क में वर्षा के पानी और जल जमाव के प्रति मजबूती और बेहतर प्रतिरोध नज़र आया। इसको स्थायी एवं प्रतिकृति योग्य बनाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की गई। पोलिथीन/प्लास्टिक कैरी बैगों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए मसौदा अधिसूचनाएं जारी की गई थीं।

चरण–II (दिसम्बर' 09 – मार्च' 2010) – जागरूकता बढाना और पहल को व्यापक आधार प्रदान करना: एक दो चरणीय ''पोलिथीन हटाओ–पर्यावरण बचाओ'' अभियान पर विचार किया गया। चरण एक में स्वैच्छिक सफाई चलाई गयी। तुकबंदियों, वीडियो कतरनों, और वृत–चित्र फिल्मों आदि का प्रयोग करके आम जनता को संवेदनशील बनाया गया। चरण–II में, चरण–I का मूल्यांकन किया गया और उपायुक्त द्वारा राज्य सरकार को

Initiative - Sustainable Plastic Waste Management in Himachal Pradesh: From Concept to Policy

Name of the Organization - Department of Environment, Science and Technology (DEST), Government of Himachal Pradesh

The GoHP had undertaken proactive role and initiatives towards awareness-generation, action and advocacy to preserve and protect the environment. In the wake of rapid population growth, urbanization, industrialization and other development imperatives, implementation of the initiative posed a big challenge. In April 2009, the GoHP decided to work towards a comprehensive "Sustainable Plastic Waste Management Plan" to control the use of plastic and its disposal.

The initiative was undertaken in three stages:

Stage-I (Apr' 09 - Nov' 09) - Creating an enabling framework: For technological solution, DEST with experts from Central Road Research Institute, Delhi, worked out a cost-effective technology of use of plastic in road construction as a result of which the road showed increased strength and better resistance to rain water and water stagnation. To make it sustainable and replicable, a comprehensive plan was developed. Draft notifications imposing complete ban on use of polythene / plastic carry bags were issued.

Stage-II (Dec' 09- Mar' 2010) - Enhancing awareness & broad-basing the initiative: A two phase "Polythene Hatao – Paryavaran Bachao" campaign was conceived. In Phase-I, voluntary cleaning was carried out. General public was sensitized by use of jingles, video clippings, and documentary films, etc. In Phase-II, the performance of Phase-I was evaluated, and outcome was submitted to the State Government by the Deputy

परिणाम प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर बेहतर कार्य निष्पादन करने वाले जिलों/पंचायतों की पहचान की गई।

चरण-III (अप्रैल' 10 - जारी) सम्मेलन एवं स्थायीत्व: (क) उपायुक्तों द्वारा सभी संग्रहण केन्द्रों अधिसूचना; (ख) संग्रहण केन्द्रों से सहबद्ध गैर सरकारी संगठनों, संस्थाओं, द्वार से द्वार संग्राहकों का उपायुक्तों द्वारा पंजीकरण; (ग) कचरा उठाने के लिए लागू की गई भुगतान शर्तों पर संग्रहण केन्द्रों से कचरा उठाने का निरीक्षण करने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा कनिष्ठ अभियंताओं का नामांकन; (घ) संग्रह किए गए कचरे की मात्रा का रिकार्ड रखा जाए; (ड) पूरे राज्य में पक्की की जाने वाली सड़कों के विस्तारों की लोक निर्माण विभाग द्वारा पहचान; और (च) प्लास्टिक का संग्रहण/हॉट स्पॉटों की सफाई पर निर्णय लेने के लिए लोक निर्माण विभाग (पी डब्ल्यू डी); पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ बैठकें आयोजित की गई।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने ''स्थायी प्लास्टिक कचरा प्रबंध योजना'' के जरिए प्लास्टिक खतरे की चुनौती का सामना करने के लिए सफलतापूर्वक प्रणाली विकसित की और इसे कार्यान्वित किया तथा पूरे राज्य में इसे अपनाया। इस प्रकार, प्लास्टिक कैरी बैगों की सकल विलुप्तता, नागरिकों में जागरूकता और स्वच्छ हिमाचल को प्राप्त किया जा सका। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सड़क की 35, 000 रूपयें से 40, 000 रूपये प्रति कि.मी. तक सड़क निर्माण की लागत बचत का एक अतिरिक्त लाभ प्राप्त किया गया।

Commissioners based on which, the best performing Districts / Panchayats were identified.

Stage-III (Apr' 10 - ongoing) - Consolidation and Sustainability: Meetings were held with Public Works Department (PWD), DEST and Additional Chief Secretary (Environment) to decide on – (a) Notification of all collection centres by the Deputy Commissioners; (b) Registration by the Deputy Commissioners of the NGOs, organizations, institutions, door-to-door waste collectors affiliated with the collection centres; (c) Nomination of Junior Engineers by the PWD for overseeing the lifting of waste from the collection centers with payment terms for lifting having been decided; (d) Records to be maintained on the quantity of waste collected; (e) Identification by PWD of stretches of road to be metalled throughout the state; and (f) Collection of plastics/cleaning of hot spots.

GoHP successfully developed and implemented the system to meet the challenge of plastic menace through the "Sustainable Plastic Waste Management Plan" and adopted it throughout the state. Thus, total disappearance of plastic carry-bags; awareness among citizens and cleaner Himachal could be achieved. Cost-saving in the road construction up to Rs. 35,000 to Rs. 40,000 per km of road was an additional benefit realised by the GoHP.

दिनांक 21 अप्रैल, 2010 को प्रदान किए गए वर्ष 2008-09 के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार

1.	**पहल** -	**ढ़ाँचों का अतिक्रमण हटाना - सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना, जबलपुर, मध्य प्रदेश**
	पुरस्कार विजेता का नाम :	श्री संजय दुबे, भा. प्र. से., तत्कालीन समाहर्ता और जिलाधीश, जबलपुर, मध्य प्रदेश
2.	**पहल** -	**नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी, बालाघाट, मध्य प्रदेश**
	पुरस्कार विजेता का नाम :	श्री गुलशन बामरा, भा. प्र. से., तत्कालीन समाहर्ता और जिलाधीश, बालाघाट, मध्य प्रदेश
3.	**पहल** -	**औषधियों को किफायती बनाना, चित्तौड़गढ़, राजस्थान**
	पुरस्कार विजेता का नाम :	डॉ. समित शर्मा, भा. प्र. से., तत्कालीन जिलाधीश चित्तौड़गढ़, राजस्थान
4.	**पहल** -	**नदी संयोजन परियोजना, जलगांव, महाराष्ट्र**
	पुरस्कार विजेता का नाम :	श्री विजय सिंघल, भा. प्र. से., तत्कालीन समाहर्ता और जिलाधीश, जलगांव, महाराष्ट्र

Prime Minister's Awards for Excellence in Public Administration for the year 2008-09 presented on 21st April, 2010

1.	**Initiative-** Name of the Awardee:	**Removal of Encroachments of Structures - Maintaining Communal Harmony, Jabalpur, Madhya Pradesh** Shri Sanjay Dubey, IAS then Collector & District Magistrate, Jabalpur, Madhya Pradesh
2.	**Initiative-** Name of the Awardee:	**Involvement of Community in Naxalite-affected Areas, Balaghat, Madhya Pradesh** Shri Gulshan Bamra, IAS, then Collector and District Magistrate, Balaghat, Madhya Pradesh
3.	**Initiative-** Name of the Awardee:	**Making Medicines Affordable, Chittorgarh, Rajasthan** Dr. Samit Sharma, IAS, then District Magistrate, Chittorgarh, Rajasthan
4.	**Initiative-** Name of the Awardee:	**River Linking Project, Jalgaon, Maharashtra** Shri Vijay Singhal, IAS, then Collector & District Magistrate, Jalgaon, Maharashtra

5.	**पहल** – पुरस्कार विजेता का नाम :	**गर्भाशय कैंसर की जांच-** **चेन्नई, तमिलनाडु** श्री राजेश लखानी, भा. प्र. से., आयुक्त, चेन्नई निगम, तमिलनाडु
6.	**पहल** – दल के सदस्यों के नाम :	**धान की खरीद और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण, छत्तीसगढ़** 1. डॉ. आलोक शुक्ला, भा. प्र. से., तत्कालीन सचिव, एफसीएस एंड सीए विभाग 2. श्री गौरव द्विवेदी, भा. प्र. से., तत्कालीन प्रबंध निदेशक, 'मार्कफेड' और 'सीजीएससीएससी' 3. श्री ए.के. सोमशेखर, वैज्ञानिक 'घ' राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र
7.	**पहल** – दल के सदस्यों के नाम :	**वन अधिकारों को मान्यता, मध्य प्रदेश** 1. श्री ओ. पी. रावत, भा. प्र. से., प्रधान सचिव, मध्य प्रदेश सरकार 2. श्री जयदीप गोविंद, भा. प्र. से., तत्कालीन आयुक्त, जनजाति विकास 3. श्री अनिल ओबरॉय, भा. व. से., अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

5.	**Initiative-** Name of the Awardee:	**Cervical Cancer Screening, Chennai, Tamil Nadu** Shri Rajesh Lakhani, IAS, Commissioner, Corporation of Chennai, Tamil Nadu
6.	**Initiative-** Name of the Team Members:	**Computerization of Paddy Procurement and Public Distribution System, Chhattisgarh** 1. Dr. Alok Shukla, IAS, then Secretary, Department of FCS & CA 2. Shri Gaurav Dwivedi, IAS, then, Managing Director, 'MARKFED' & 'CGSCSC' 3. Shri A.K. Somasekhar, Scientist 'D', National Informatics Centre
7.	**Initiative-** Name of the Team Members:	**Recognition of Forest Rights, Madhya Pradesh** 1. Shri O.P. Rawat, IAS, Principal Secretary, Govt. of Madhya Pradesh 2. Shri Jaideep Govind, IAS, then Commissioner, Tribal Development 3. Shri Anil Oberoi, IFS, Addl. Principal Chief Conservator of Forest

		4. सुश्री रश्मि अरूण शामी, भा. प्र. से. तत्कालीन निदेशक, जनजाति क्षेत्र विकास आयोजना 5. श्री अशोक कुमार उपाध्याय, अपर निदेशक
8.	**पहल –** दल के सदस्यों के नाम :	**समन्वित करदाता आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली (आईटीडीएमएस), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, भारत सरकार** 1. श्री एस.एस. खान, भा. रा. से. (आई.टी), तत्कालीन आयकर महानिदेशक (जॉच), नई दिल्ली 2. श्री मिलाप जैन, भा. रा. से. (आई.टी.), आयकर महानिदेशक (जांच), नई दिल्ली 3. श्री जी.टी. वेंकटेश्वर राव, भा. रा. से. (आई.टी.), तत्कालीन आयकर अपर निदेशक (जांच) नई दिल्ली
9.	**पहल –** संगठन का नाम :	**''प्रोजेक्ट एरो''– भारतीय डाक की कायापलट** डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार

		4. Ms. Rashmi Arun Shami, IAS, then Director, Tribal Area Development Planning 5. Shri Ashok Kumar Upadhyay, Additional Director
8.	**Initiative-** Name of the Team Members:	**Integrated Taxpayer Data Management System (ITDMS), Central Board of Direct Taxes, Government of India** 1. Shri S. S. Khan, IRS (IT), then Director General of Income Tax (Investigation), New Delhi 2. Shri Milap Jain, IRS (IT), Director General of Income Tax (Investigation), New Delhi 3. Shri G. T. Venkateswara Rao, IRS (IT), then Additional Director of Income Tax (Investigation), New Delhi
9.	**Initiative-** Name of the Organisation:	**'Project Arrow'- Transforming India Post** Department of Posts, Ministry of Communications & IT, Government of India

दिनांक 21 अप्रैल, 2009 को प्रदान किए गए वर्ष 2007-08 के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार

1.	**पहल** -	**बंगलौर महानगर परिवहन निगम, कर्नाटक को वित्तीय सहायता**
	पुरस्कार विजेता का नाम :	श्री उपेन्द्र त्रिपाठी, भा. प्र. से., तत्कालीन प्रबंध निदेशक, बंगलौर महानगर परिवहन निगम, कर्नाटक सरकार
2.	**पहल** -	**प्राथमिक शिक्षा हेतु क्रिया आधारित विद्यार्जन (एबीएल) प्रणाली, तमिलनाडु**
	पुरस्कार विजेता का नाम :	श्री एम. पी. विजय कुमार, भा. प्र. से. तत्कालीन आयुक्त, चैन्नई नगर निगम तमिलनाडु सरकार
3.	**पहल** -	**युद्ध के दौरान बेरूत से भारतीय नागरिकों का निकास**
	पुरस्कार विजेता का नाम :	श्रीमती नेंगचा ल्होबुम, भा. वि. से. लेबनान में भारत की राजदूत
4.	**पहल** -	**सुरक्षित मातृत्व एवं बाल संरक्षण कार्यक्रम**
	पुरस्कार विजेता का नाम :	डॉ. अमरजीत सिंह, भा. प्र. से. सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, गुजरात सरकार

Prime Minister's Awards for Excellence in Public Administration for the year 2007-08 presented on 21st April, 2009

1.	**Initiative-** Name of the Awardee:	**Financial Sustainability of Bangalore Metropolitan Transport Corporation, Karnataka.** Shri Upendra Tripathy, IAS then Managing Director, Bangalore metropolitan Transport Corporation, Government of Karnataka
2.	**Initiative-** Name of the Awardee:	**Activity Based Learning (ABL) Methodology for Primary Education, Tamil Nadu** Shri M.P.Vijaya Kumar, IAS, then Commissioner of Chennai Municipal Corporation, Government of Tamil Nadu
3.	**Initiative-** Name of the Awardee:	**Evacuation of Indian Nationals from Beirut during the war** Mrs. Nengcha Lhouvum, IFS Ambassador of India in Lebanon
4.	**Initiative-** Name of the Awardee:	**Safe Motherhood and Child Survival Programme** Dr. Amarjit Singh, IAS Secretary, Health & Family Welfare Department, Government of Gujarat

5.	**पहल** – दल के सदस्यों के नाम :	**स्कोर : बिहार में ई-पंजीकरण** 1. श्री अनिल कुमार, भा. प्र. से., आईजी, पंजीकरण 2. श्री दिलीप कुमार, एआईजी पंजीकरण 3. श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह 4. श्री बरूणा नंदन सिंह 5. श्री निर्मल किशोर प्रसाद, एसएसए 6. श्री संजय कुमार, एसएसए, बिहार सरकार
6.	**पहल** – दल के सदस्यों के नाम : दल के सदस्यों के नाम :	**एमसीए 21-एक नई-गवर्नेंस परियोजना** 1. श्री अनिल कुमार, भा. प्र. से., 1. श्री अनुराग गोयल, भा. प्र. से. सचिव, एमसीए 2. श्री युद्धवीर सिंह मलिक, भा. प्र. से., तत्कालीन संयुक्त सचिव, एमसीए 3. डॉ. (सुश्री) शीला भिडे, भा. प्र. से., तत्कालीन संयुक्त सचिव, एमसीए 4. श्री आर. चंद्रशेखर, भा. प्र. से. तत्कालीन अपर सचिव (आई.टी.) 5. श्री जितेश खोसला, भा. प्र. से., संयुक्त सचिव, एमसीए 6. श्री एस. श्रीधरन, कनिष्ठ विश्लेषक, एमसीए, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

5.	**Initiative-** Name of the Team Members:	**SCORE: e-Registration in Bihar** 1. Shri Anil Kumar, IAS, IG Registration 2. Shri Dilip Kumar, AIG Registration 3. Shri Birendra Kumar Singh 4. Shri Baruna Nandan Singh 5. Shri Nirmal Kishor Prasad, SSA 6. Shri Sanjay Kumar, SSA Government of Bihar
6.	**Initiative-** Name of the Team Members:	**MCA21 – an e-Governance Project** 1. Shri Anurag Goel, IAS, Secretary, MCA 2. Shri Yudhvir Singh Malik, IAS, then JS, MCA 3. Dr.(Ms.) Sheela Bhide, IAS, then JS, MCA 4. Shri R.Chandrashekhar, IAS, then AS (IT) 5. Shri Jitesh Khosla, IAS, JS, MCA 6. Shri S.Sridharan, JA, MCA, Ministry of Corporate Affairs, Government of India

7.	**पहल** – दल के सदस्यों के नाम :	**बेहतर स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अभ्यास, जिला–सरगुजा, छत्तीसगढ़** 1. डॉ. रोहित यादव, भा. प्र. से., जिला अधिकारी 2. सुश्री रितु सेन, भा. प्र. से., जिला अधिकारी (डी एवं आर) जिला: सरगुजा, छत्तीसगढ़ सरकार
8.	**पहल** – दल के सदस्यों के नाम :	**मणिपुर में कार्मिक सूचना प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण** 1. श्री जरनैल सिंह, भा. प्र. से., तत्कालीन प्रधान सचिव 2. श्री आर. आर. रश्मि, भा. प्र. से. 3. श्री एस. सुंदरलाल सिंह, भा. प्र. से. 4. श्री के. राधाकुमार सिंह, भा. प्र. से. 5. श्रीमती एम. बुद्धिमाला देवी 6. श्रीमती ओ. शालिजा चनु मणिपुर सरकार
9.	**पहल** – संगठन का नाम :	**जोखिम प्रबंध प्रणाली (आरएमएस) का कार्यान्वयन** प्रणाली तथा आँकड़ा प्रबंधन महानिदेशालय केंद्रीय उत्पाद तथा सीमाशुल्क बोर्ड, भारत सरकार

7.	**Initiative-** Name of the Team Members:	**Improved Health and Sanitation Practices, District Surguja, Chhattisgarh** 1. Dr. Rohit Yadav, IAS, District Collector 2. Ms. Ritu Sain, IAS, DC (D&R) District : Surguja, Government of Chhattisgarh
8.	**Initiative-** Name of the Team Members:	**Computerization of Personnel Information System in Manipur** 1. Shri Jarnail Singh, IAS, then Chief Secretary 2. Shri R.R.Rashmi, IAS 3. Shri S.Sunderlal Singh, IAS 4. Shri K. Radhakumar Singh, IAS 5. Smt. M.Budhimala Devi 6. Smt. O.Shaliza Chanu Government of Manipur
9.	**Initiative-** Name of the Organisation:	**Implementation of the Risk Management System(RMS)** Directorate General of Systems & Data Management, Central Board of Excise and Customs, Government of India

दिनांक 21 अप्रैल, 2008 को प्रदान किए गए वर्ष 2006-07 हेतु लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार

1.	**पहल –**	**त्रिची सामुदायिक पुलिस व्यवस्था**
	पुरस्कार विजेता का नाम :	श्री जे.के. त्रिपाठी, भा. पु. से., पुलिस महानिरीक्षक आर्थिक अपराध स्कन्ध तमिलनाडु सरकार
2.	**पहल –**	**मातृत्व एवं बाल संरक्षण तथा स्वास्थ्य में सुधार करना (तमिलनाडु)**
	पुरस्कार विजेता का नाम :	सुश्री शीला रानी चुकंट, भा. प्र. से., अध्यक्ष तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड
3.	**पहल –**	**ठाणे एवं नागपुर (महाराष्ट्र) शहरों का बदला स्वरूप**
	पुरस्कार विजेता का नाम :	डॉ. टी. चन्द्रशेखर, भा. प्र. से., उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र आवास तथा क्षेत्र विकास प्राधिकरण, मुंबई
4.	**पहल –**	**लोकवाणी–नागरिकों को अधिकारिता देने का एक प्रयास (उत्तर प्रदेश)**
	दल के सदस्यों का नाम :	(i) श्री आमोद कुमार, भा. प्र. से. (ii) सुश्री जोहरा चटर्जी, भा. प्र. से. (iii) श्री एस.बी. सिंह

Prime Minister's Awards for Excellence in Public Administration for the year 2006-07 presented on 21st April, 2008

1.	**Initiative-** Name of the Awardee:	**Trichy Community Policing** Shri J.K.Tripathy, IPS Inspector General of Police Economic Offences Wing Government of Tamil Nadu
2.	**Initiative-** Name of the Awardee:	**Improving Maternal and Child Survival and Health (Tamil Nadu)** Ms. Sheela Rani Chunkath, IAS Chairperson, Tamil Nadu Industrial Investment Corporation Ltd.
3.	**Initiative-** Name of the Awardee:	**Changing Face of Thane & Nagpur Cities (Maharashtra)** Dr. T.Chandra Shekar, IAS Vice President & CEO, Maharashtra Housing & Area Development Authority, Mumbai
4.	**Initiative-** Name of the Team Members :	**Lokvani-an effort to empower the Citizen (Uttar Pradesh)** (i) Shri Amod Kumar, IAS (ii) Ms. Zohra Chaterjee, IAS (iii) Shri SB Singh

		(iv) श्री उमा शंकर सिंह (v) श्री देवेन्द्र पाण्डे (vi) श्री ए.पी. सिंह
5.	**पहल** – दल के सदस्यों का नाम :	**सूचना प्रौद्योगिकी लेखा परीक्षा पहल** (i) श्री गौतम गुहा, भा.ले. तथा ले.प. सेवा (ii) श्री एल.एस. सिंह, भा.ले. तथा ले.प. सेवा (iii) श्री राजेश गोयल, भा.ले. तथा ले.प. सेवा (iv) श्री नीलेश कुमार शाह, भा.ले. तथा ले.प. सेवा (v) डॉ. आशुतोष शर्मा, भा.ले. तथा ले.प. सेवा
6.	**पहल** – दल के सदस्यों का नाम :	**संरक्षित क्षेत्रों का कारगर प्रबंधन–उत्तराखंड** (i) सुश्री ज्योत्सना स्टिलिंग, भा.वन.से. (ii) श्री ए.के. बनर्जी, भा.वन. से.
7.	**पहल** – दल के सदस्यों का नाम :	**अनारक्षित टिकट प्रणाली– रेल मंत्रालय** 1. श्री विक्रम चोपड़ा, आई आर टी एस 2. डॉ. राजेश नारंग 3. श्री टी वेंकटसुब्रमणियन् आईआरएस एमई 4. श्री आर चन्द्रशेखर 5. श्री रमन बंसल 6. सुश्री मोनिका मल्होत्रा 7. श्री आलोक चतुर्वेदी आई आर टी एस

		(iv) Shri Uma Shankar Singh (v) Shri Devendra Pande (vi) Shri A P Singh
5.	**Initiative-** Name of the Team Members:	**Information Technology Audit Initiative** (i) Shri Gautam Guha, IA&AS (ii) Shri L S Singh, IA&AS (iii) Shri Rajesh Goel, IA&AS (iv) Shri Neelesh Kumar Sah, IA&AS (v) Dr. Ashutosh Sharma, IA&AS
6.	**Initiative-** Name of the Team Members:	**Effective Management of Protected Areas – Uttarakhand** (i) Ms. Jyotsna Sitling, IFS (ii) Shri A.K.Banerjee, IFS
7.	**Initiative-** Name of the Team Members:	**Unreserved Ticketing System – Ministry of Railways** 1. Shri Vikram Chopra, IRTS 2. Dr. Rajesh Narang 3. Shri T. Venkatasubramanian IRSME 4. Shri R.Chandrashekar 5. Shri Raman Bansal 6. Ms. Monica Malhotra 7. Shri Alok Chaturvedi IRTS

		8. श्री टी किरण कुमार 9. श्री कौस्तव मंडल 10. श्री देबाशीष घोष 11. श्री जी.जे. जैरी औरिक सिंह 12. श्री कपिल भगत 13. श्री प्रोजिनेश विस्वास 14. श्री दिलीप मिश्रा 15. श्री संदीप कुमार वत्स 16. श्री आशीष अरोड़ा 17. श्री गौरव डी. जौहरी 18. श्री नितिन गोयल 19. श्री पंकज कुमार 20. श्री आशीष विश्वकर्मा 21. श्री गौरव जैन 22. श्री बालू लाल धाकड़ 23. श्री रीतेश लाल 24. श्री प्रेम कुमार 25. श्री महेन्दर जे. दुबे 26. श्री मोहम्मद शाहिद 27. श्री अंजनी कुमार मलिक 28. श्री दर्शन
8.	**पहल** – दल के सदस्यों के नाम :	**राजर्षि शाहू सर्वांगीण कार्यक्रम, जिला परिषद्, कोल्हापुर, महाराष्ट्र** (i) श्री देशमुख प्रभाकर कृष्ण जी, भा.प्र.से. (ii) श्री माने महावीर दामोदर

		8. Shri T.Kiran Kumar 9. Shri Kaustav Mandal 10. Shri Debashish Ghosh 11. Shri G.J.Jerrie Auric Singh 12. Shri Kapil Bhagat 13. Shri Projinesh Biswas 14. Shri Dileep Mishra 15. Shri Sandeep Kumar Vats 16. Shri Ashish Arora 17. Shri Gaurav D. Johari 18. Shri Nitin Goyal 19. Shri Pankaj Kumar 20. Shri Ashish Vishwakarma 21. Shri Gaurav Jain 22. Shri Balu Lal Dhaker 23. Shri Ritesh Lal 24. Shri Prem Kumar 25. Shri Mahender J Dubey 26. Shri Mohd. Shahid 27. Shri Anjani Kumar Malik 28. Shri Darshan
8.	**Initiative-** Name of the Team Members:	**Rajarshi Shahu Sarvangin Karyakram, Zilla Parishad, Kolhapur, Maharashtra** (i) Shri Deshmukh Prabhakar-Krishnaji,IAS (ii) Shri Mane Mahavir Damodar

9.	**पहल –** दल के सदस्यों के नाम :	**दिल्ली सरकार विद्यालय पद्धति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार में मूलभूत सुधार** (i) श्री राजेन्द्र कुमार, भा.प्र.से. (ii) श्री विजय कुमार, भा.प्र.से. (iii) श्रीमती गीतांजली जी कुन्द्रा, भा.प्र.से. (iv) श्री अशोक कुमार
10.	**पहल –** दल के सदस्यों के नाम :	**जम्मू और कश्मीर राज्य में भूकम्प की आपातिक स्थिति में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन** (i) श्री बी.बी. व्यास, भा.प्र.से. (ii) श्री बशरत अहमद धर, भा.प्र.से (iii) श्री बशीर अहमद रुनियाल, भा.प्र.से. (iv) श्री अब्दुल मजीद खाण्डेय, क.प्र.से. (v) श्री जयपाल सिंह, क.प्र.से. (vi) श्री सईद शरीफ-उद्-दीन, क.प्र.से. (vii) श्री मोहम्मद रमजान ठाकुर, क.प्र.से.
11.	**पहल –**	**जल और स्वच्छता प्रबंध संगठन (डब्ल्यू ए एस एम ओ) – ''गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में नवीनतम भागीदारी पेय जल प्रदायगी पहुंच'' –गुजरात सरकार**

9.	**Initiative-** Name of the Team Members:	**Radical Improvement in Delhi Government School System, Government of NCT of Delhi** (i) Sh. Rajendra Kumar, IAS (ii) Sh. Vijay Kumar, IAS (iii) Smt. Gitanjali G Kundra, IAS (iv) Sh. Ashok Kumar
10.	**Initiative-** Name of the Team Members:	**Extraordinary Performance in Emergent Situation of Earthquake in the State of J&K.** (i) Shri B.B.Vyas, IAS (ii) Shri Basharat Ahmad Dhar, IAS (iii) Shri Bashir Ahmad Runiyal, IAS (iv) Shri Abdul Majid Khanday, KAS (v) Shri Jai Pal Singh, KAS (vi) Shri Syed Sharief-ud-din, KAS (vii) Shri Mohammad Ramzan Thakur, KAS
11.	**Initiative-**	**Water & Sanitation Management Organisation (WASMO) – 'Innovative Participatory Drinking Water Delivery Approach in Rural Areas of Gujarat' – Government of Gujarat**

12.	पहल –	राज्य गरीबी उन्मूलन अभियान, कुडुम्बश्री–''आश्रय - निराश्रय की पहचान, पुनर्वास और मॉनीटरिंग परियोजना''– केरल सरकार
13.	पहल –	इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवायें (ई-सेवा)– आंध्र प्रदेश सरकार
14.	पहल –	उड़ीसा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण, (ओपीईपीए)– ''उड़ीसा में बाल खोज प्रणाली''–उड़ीसा सरकार

12.	**Initiative-**	**State Proverty Eradication Mission, Kudumbashree – 'Asraya – Destitute Identification, Rehabilitation and Monitoring Project' - Government of Kerala**
13.	**Initiative-**	**Electronically Deliverable Services (e-Seva) – Government of Andhra Pradesh.**
14.	**Initiative-**	**Orissa Primary Education Programme Authority (OPEPA) – 'Child Tracking System in Orissa'- Government of Orissa**

दिनांक 21 अप्रैल, 2007 को प्रदान किये गये वर्ष 2005-06 हेतु लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार

1. श्री राजीव चावला, भा.प्र.से. – ''भूमि-कर्नाटक में भूमि अभिलेखों की ऑनलाइन प्रदायगी'' पहल हेतु।

2. श्री आर. एस. पाण्डेय, भा.प्र.से. – ''नागालैंड में सार्वजनिक संस्थानों और सेवाओं के सामुदायिकीकरण का कार्यक्रम'' पहल हेतु।

Prime Minister's Awards for Excellence in Public Administration for the year 2005-06 presented on 21st April, 2007

1. Shri Rajeev Chawla, IAS – for the initiative “Bhoomi – Online delivery of land records in Karnataka".

2. Shri R.S.Pandey, IAS – for the initiative “Programme of Communitization of Public Institutions and Services in Nagaland”.